

प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर हुआ 3.92 प्रतिशत

चर्चा में क्यों

15 मार्च, 2023 को राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत था, जो वर्तमान में बढ़कर 3.92 प्रतिशत हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि विधानसभा ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 16 अरब 78 करोड़ 24 लाख 36 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनित से पारित कर दी हैं।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7 प्रतिशत वन क्षेत्र है। सरकार द्वारा नई वन नीति का अनुमोदन कर 20 प्रतिशत भूमि को वन अक्षांशित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- वन मंत्री ने अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 में 56 हजार 410 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाएगा।
- हेमाराम चौधरी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 9 नये कन्जर्वेशन रजिस्टर घोषित किये गए हैं। रणथम्भौर, सरसिका एवं मुकुंदरा टाइगर हिल्स के बाद रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को चौथे टाइगर रजिस्टर के रूप में वकिसति किया जा रहा है। इसके अलावा धौलपुर में एक टाइगर रजिस्टर को अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- उन्होंने बताया कि वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों तथा जन सहयोग से 'ट्री आउट साइड फोरेस्ट इन राजस्थान' नाम से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार कर वितरित किये जाएंगे।
- वन मंत्री ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका वकिसति की जा रही है तथा वर्ष 2023-24 में हर जिले में एक-एक लव कुश वाटिका और वकिसति की जाएगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में आगामी वर्ष में 32 करोड़ रुपये के कार्य कराकर ग्रीन लंग्स क्षेत्र वकिसति किये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि राज्य के टाइगर रजिस्टरों से ग्रामों के सवैच्छिक वसिस्थापन कार्य को भी गति प्रदान की गई है। सरसिका टाइगर रजिस्टर व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रजिस्टर से तीन-तीन गाँव तथा रणथम्भौर टाइगर रजिस्टर से एक गाँव पूर्णतया वसिस्थापित कर दिये गए हैं।
- हेमाराम चौधरी ने बताया कि राज्य में वन्य जीव प्रेमियों, संस्थाओं तथा कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा जैविक उद्यानों में वास करने वाले वन्य जीवों को गोद लेने के लिये केपेटिव एनमिल स्पोसर स्कीम प्रारंभ की गई है।
- उन्होंने बताया कि राज्य के संरक्षित क्षेत्रों हेतु 24 स्थानों में से 15 क्षेत्रों को इको सेंसेटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।
- वर्ष 2023-24 में फ़रास सरकार के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1 हजार 693 करोड़ की राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी तथा जाइका के सहयोग से एक हजार 803.42 करोड़ रुपये की एक परियोजना राज्य के 19 जिलों के लिये तैयार की जा रही है।